



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 03 अक्टूबर, 2003 ई0

आश्विन 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

सहकारिता विभाग

संख्या 503/अ0स0श0/2003

देहरादून, 03 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

विविध

प0 आ0-148

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सहकारिता विभाग, तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सहकारिता विभाग, तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2003

भाग एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) यह नियमावली "उत्तरांचल सहकारिता विभाग, तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2003" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- सेवा की प्रास्थिति :

उत्तरांचल सहकारिता विभाग तृतीय वर्ग सेवा अधीनस्थ अराजपत्रित एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

3-परिभाषाएं :

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

- (क) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य अपर निबन्धक से है;
- (ख) "अपर निबन्धक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो सरकार द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल के प्रधान कार्यालय में अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल के रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
- (घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
- (ङ) "विभाग" का तात्पर्य सहकारिता विभाग उत्तरांचल सरकार से है;
- (च) "उपनिबन्धक" का तात्पर्य उपनिबन्धक सहकारी समितियां, उत्तरांचल से है;
- (छ) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-15 में निहित रीति की भर्ती से है;
- (ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (ञ) "समूह तीन" के अन्तर्गत राजकीय पर्यवेक्षक, और ऐसे अन्य पद जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में घोषित किये जायें, धारण करने वाले अधिकारी से भी है;
- (ट) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
- (ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम नहीं है तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय किसी प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ड) "निबन्धक" का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथापरिभाषित निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल से है;
- (ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य जिस वर्ष भर्ती की जाये उस कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;
- (ण) "कर्मचारी वर्ग" का तात्पर्य विभाग के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों से है;
- (त) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारिता विभाग, तृतीय वर्ग अधीनस्थ सेवा से है।

भाग दो—संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग :

- (1) सेवा के सदस्यों की और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) सेवा के सदस्य और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट की गयी है :

परन्तु—

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आगे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और
- (ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन-भर्ती

5-भर्ती स्रोत :

इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में पदों पर भर्ती सीधी भर्ती से की जायेगी।

6-आरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-अर्हताएं

7-राष्ट्रीयता :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका एवं केनिया, उगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु—

उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु—

यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु—

यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8-शैक्षिक अर्हताएं :

समूह तीन के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु राजकीय पर्यवेक्षक पद के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिये।

9-अधिमानी अर्हता :

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्होंने कि —

(क) नेशनल कैडेट कोर का "ख" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10-आयु :

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उत्तरांचल सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी आयु सीमा के अनुसार होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11-चरित्र :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे।

12-वैवाहिक प्रारिथति :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13-शारीरिक स्वस्थता :

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन, के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

14-रिक्तियों की अवधारणा :

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

15-सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

(1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी:-

(क) दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(ख) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर सूचना विपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन या अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(2) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और अन्य मूल्यांकन के परिणाम को सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुनी होगी।

(4) किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों से जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

(6) पाठ्य विवरण—

प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

(7) चयन समिति का गठन—

सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी पदेन अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा सदस्य

(चार) दो उपनिबन्धक जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे सदस्य

भाग छ:—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16—नियुक्ति :

मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथारिथति, नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो, नियुक्तियां करेगा।

17—परीक्षा :

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये: परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवायें समाप्त की जाएं, किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।

- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

18-स्थायीकरण :

किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परीक्षा अवधि के अंत में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

- (क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो;
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो; और
- (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

19-ज्येष्ठता :

सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो।

टिप्पणी— सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्यकरण के कारण कार्यभार ग्रहण न करे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग सात—वेतन आदि

20—वेतनमान :

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थायी रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के अनुमन्य, वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

21—परीक्षा अवधि में वेतन :

- (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परीक्षाधीन व्यक्ति का, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी गयी हो तो अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन उन सुसंगत-नियमों द्वारा विनियमित होगा जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

22—पक्ष समर्थन :

किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

23—अन्य विषयों का विनियमन :

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों से नियंत्रित होंगे।

24—सेवा की शर्तों में शिथिलता :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्यक पूर्ण ढंग से निपटाने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

25—व्यावृत्ति :

इस नियमावली की किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

सेवा के सदस्यों की और उनके पदों की वर्तमान संख्या

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	समूह—तीन राजकीय पर्यवेक्षक	3200—4900	176

आज्ञा से,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 503/A.S.Sh./2003, dated October 03, 2003.

NO. 503/A.S.Sh./2003

Dated Dehradun, October 03, 2003

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders of the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Co-operative Department, Group III Subordinate Service :

THE UTTARANCHAL CO-OPERATIVE DEPTT., GROUP III SUBORDINATE SERVICE RULES, 2003

PART I--GENERAL

1. Short title and Commencement :

- (i) These rules may be called "The Uttaranchal Co-operative Department, Group-III, Subordinate Service Rules, 2003".
- (ii) They shall come into force at once.

2. Status of the Service :

The Uttaranchal Co-operative Department, Group-III, Service is a State Non-Gazetted service comprising Group 'C' posts.

3. Definitions :

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context --

- (a) "Appointing Authority" means the Additional Registrar ;
- (b) "Additional Registrar" means an officer appointed by the Government as Additional Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal, at the Head Office of the Registrar, Co-operative Societies, Uttaranchal;
- (c) "Citizen of India" means that person who is the citizen of India under Part-II of the Constitution of India ;
- (d) "Constitution" means the "Constitution of India" ;
- (e) "Department" means Co-operative Department, Uttaranchal ;
- (f) "Deputy Registrar" means "Deputy Registrar Co-operative Societies, Uttaranchal" ;
- (g) "Direct Recruitment" means recruitment in the manner prescribed under Rule 15;
- (h) "Government" means the State Government of Uttaranchal ;
- (i) "Governor" means the Governor of Uttaranchal ;
- (j) "Group -III" means Government Supervisors, and such other posts as may be declared by the State Government from time to time ;
- (k) "Member of Service" means a person appointed in a substantive capacity under these rules or under the provisions of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;
- (l) "Substantive appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rules and if there

were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

- (m) "Registrar" means the "Registrar, Co-operative Societies", Uttaranchal as defined under sub-section (1) of section 3 of the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003;
- (n) "Year of recruitment" means the period of twelve months beginning from 1st day of July of the calendar year in which a recruitment is made;
- (o) "Employees" means Group -III employees ;
- (p) "Service" means the Co-operative Department Group -III Subordinate Sservice.

PART II--CADRE

4. Strength of Service :

- (i) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.
- (ii) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (i), shall be as specified in Appendix 'A' to these rules :

Provided that --

- (a) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; and
- (b) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, from time to time, as he may consider necessary.

PART III--RECRUITMENT

5. Source of Recruitment :

Subject to the provisions of this service rules recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the direct recruitment.

6. Reservation :

Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV--QUALIFICATIONS

7. Nationality :

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be --

- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that --

A candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE : A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary out the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualifications :

For direct recruitment to posts in the Group-III cadre of the service Government Supervisors must passed the Intermediate examination of the Uttaranchal Vidhyalayee Shiksha Evam Pariksha Parishad, U.P. Madhyamik Shiksha Parishad or an examinations declared by the Governor as equivalent thereto and possesses primary knowledge of computer.

9. Preferential Qualifications :

A candidate who has --

- (i) Obtained 'B' certificate of National Cadet Corps,
- (ii) Obtained certificate of National Service Scheme, shall other things equal be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age :

The age for direct recruitment shall be as such declared by Government of Uttaranchal time to time: Provided that --

The upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character :

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE --Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status :

A male candidate who has more than one wife living of a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that --

The Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness :

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate to fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III:

Provided that --

A medical certificate to fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. Determination of Vacancies :

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other categories in accordance with rule 6.

15. Procedure for Direct Recruitment :

1. For making direct recruitment the vacancies shall be notified in the following manner :--
 - (a) By publishing the application form in two daily news papers having wide circulation;
 - (b) By pasting the notice on the notice-board of the office or by advertising through radio/television and other employment news papers; and
 - (c) By notifying vacancies to the employment exchange.
2. The application shall be invited for consideration for selection in the form published under sub-rule(1).
3. After the result of the written examination and other evaluations have been received and tabulated, the Selection Committee shall having regard provisions of reservation referred to in Rule 6, hold an interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies.
4. The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the members of the Selection Committee separately.
5. The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination. The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of vacancies.
6. **Syllabus--**
The syllabus and the rules of the competitive examination shall be as such prescribed by the Government from time to time.

7. Constitution of Selection Committee --

The direct recruitment shall be made by a Selection Committee consisting of--

- (i) Appointing Authority ... Ex-officio Chairman
- (ii) An officer belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman ... Member
- (iii) An officer belonging to Other Backward Classes, shall be nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to the Other Backward Classes. If the Chairman belongs to the Other Backward Classes an officer other than other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman ... Member
- (iv) Two Deputy Registrar nominated by the Appointing Authority ... Member

PART VI--APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

16. Appointment :

On the occurrence of substantive vacancies, the Appointing Authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under Rule 15, as the case may be.

17. Probation :

- (1) A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted :

Provided that --

Save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

- (3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or the extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

18. Confirmation :

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

- (a) he has successfully undergone the prescribed training, if any;
- (b) his work and conduct is reported to be satisfactory;
- (c) his integrity is certified; and
- (d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

19. Seniority :

The inter seniority of persons directly appointed to the service shall be same as determined at the time of selection:

NOTE: A person recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons will be final.

PART VII--PAY ETC.**20. Scales of Pay :**

- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay, at the time of commencement of these rules, admissible to various categories of posts in the service, are given in Appendix 'A' to these rules.

21. Pay during Probation :

- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed Departmental Examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service, when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that --

If the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that --

If the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII--OTHER PROVISIONS

22. Canvassing :

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

23. Regulation of other Matters :

In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

24. Relaxation from the Conditions of Service :

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such an extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

25. Saving :

Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be given to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time.

APPENDIX 'A'

NO. OF MEMBERS AND THEIR POSTS OF SERVICE

Sl. No.	Name of the post	Scale of Pay	No. of Posts
	<u>Group--III</u>		
1.	Government Supervisor	3200--4900	176

By Order,

VIBHA PURI DAS,

Principal Secretary.